भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2845

10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **तेलंगाना में प्राकृतिक खेती का कार्यान्वयन**

2845. श्री कुंदुरु रघुवीरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन' (एनएमएनएफ) और अन्य संबद्ध कार्यक्रमों जैसी योजनाओं के अंतर्गत देशभर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) तेलंगाना में प्राकृतिक खेती के लिए शामिल किया गया कुल क्षेत्रफल, नामांकित किसानों की संख्या और खेती को बढ़ावा देने के लिए पहचाने गए जिलों सहित कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तेलंगाना के लिए कोई वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण पहल या प्रदर्शन क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने प्राकृतिक खेती पद्धतियों के अंतर्गत उपज की पैदावार, लागत में कमी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार और बाजार से जुड़ी सहायता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): यूनियन कैबिनेट ने **25** नवंबर को नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (**NMNF)** को एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर मंज़ूरी दी**,** जिसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

(ख) एवं (ग): सरकार तेलंगाना राज्य सहित पूरे देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एनएमएनएफ योजना लागू कर रही है। एनएमएनएफ को क्लस्टर मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है। तेलंगाना के 32 जिलों में 24736.32 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 489 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत 61,125 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके)/कृषि विश्वविद्यालयों (एयू)/स्थानीय प्राकृतिक कृषि संस्थानों (एलएनएफआई) में 978 कृषि सखियों/सामुदायिक रिसोर्स पर्सन्स (सीआरपी) को प्रशिक्षित किया जा चुका है। स्थानीय स्तर पर एनएफ इनपुट के उत्पादन और आपूर्ति के लिए 315 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य को 17.955 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1323.51 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

(घ): अखिल भारतीय प्राकृतिक कृषि नेटवर्क के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 16 राज्यों में फैले 20 सहयोग केंद्रों के साथ प्राकृतिक कृषि के लिए पद्धतियों का एक पैकेज विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम में 11 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 8 आईसीएआर संस्थान/केंद्र और 1 डीम्ड विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। अनुसंधान के परिणाम सॉयल हेल्थ सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार दर्शाते हैं। 2-3 वर्षों में, प्राकृतिक कृषि भूखंडों में मृदा ऑर्गेनिक कार्बन (एसओसी) का स्तर बढ़ता हुआ देखा गया - उदाहरण के लिए, हिमालयी परीक्षणों में एसओसी लगभग 0.90% से बढ़कर 1.15% हो गया। शोध के परिणामों से यह भी पता चलता है कि प्रमुख फसलों में जैविक खेती के लिए उपयुक्त किस्मों के साथ-साथ 80 फसल प्रणालियों के लिए जैविक खेती पैकेज राज्यों के लिए उपयुक्त हैं। जैविक खेती से सॉयल हेल्थ में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, और सभी फसल श्रेणियों में जैविक और परिवर्तनशील ("जैविक की ओर") प्रणालियों की तुलना में एसओसी का स्तर लगातार उच्च रहा।

प्राकृतिक कृषि मानकों के अनुरूप सभी प्राकृतिक कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु "पीजीएस-इंडिया नेचुरल" के रूप में प्राकृतिक कृषि प्रमाणीकरण प्रणाली (एनएफसीएस) की शुरुआत की गई है। यह एक ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक कृषि केंद्र (एनसीओएनएफ) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अब तक 14 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक कृषि प्रमाणीकरण प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं और 6 लाख से अधिक किसानों को एनएफसी प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। प्रमाणीकरण से किसानों को प्राकृतिक उत्पादों का प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

*****